हिमाचल का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक समाचार पत्र

आप का सामना

हक़ीक़त से

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब,चंडीगढ़,दिल्ली, में प्रसारित

पोस्टल रजि.नंबर एचपी/33/ एसएमएल
(31 दिसंबर 2024 तक मान्य)

वर्ष- 14 अंक-27 शिमला शुक्रवार,19 l: 25 viy 2024 आरएनआई एचपीएवआईएन@2010@41180 कुल पृष्ठ-6 मूल्य- 5 रू०

आंबेडकर जयंती पर मनाली में 52 लोगों की आंखें जांची, 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया

vkdlk eukyh@iryhdgyA संविधान निर्माता डॉ. भीम राव आंबेडकर की जयंती पर मनाली में रविवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रक्तदान और नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया।इसके अलावा भंडारा भी लगाया। संविधान निर्माता डॉ. भीम राव आंबेडकर जयंती पर मनाली के रामबाग में आयोजित कार्यक्रम में मनाली के नेत्र चिकित्सक एवं समा. जसेवी डॉ. वाईके विनायक ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने डॉ. आंबेडकर के जीवन से सीख लेकर सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने पर बल दिया। कहा कि हम सभी भारतीय डॉ. आंबेडकर के ऋणी हैं। मनाली में यह कार्यक्रम भीमराव आंबेडकर वेलफेयर और नव युवा वाल्मीकि समिति मनाली ने आयोजित किया।

कार्यक्रम मालरोड में होना था लेकिन बारिश के कारण कार्यक्रम रामबाग में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विनायक नेत्रधाम मनाली की ओर से निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें 52 लोगों की आंखों की जांच की। रक्तदान शिविर में लगभग 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। मालरोड में राहगीरों को भंडारा परोसा गया।

पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और डॉ. भीम राव आंबेडकर की जीवनी पर आधारित भाषण प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें स्कूली छात्र–छात्राओं ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। नव युवा मंडल के अध्यक्ष लकी ने समारोह के आयोजन में सहायता करने वाली संस्थाओं का आभार प्रकट किया। वहीं, ब्रांण गांव में भी आंबेडकर जयंती मनाई गई।

इसमें मनाली ब्लॉक कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष पुने राम मुख्यातिथि रहे।

महिलाओं को किया अपमानित भाजपा ने 1500 रुपये रुकवाकर : कांग्रेस

vkdlk f'keykA राजस्व एवं बाग. वानी मंत्री जगत सिंह नेगी और विधानसभा में डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि भाजपा ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के 1500 रुपये रुकवाकर महिलाओं को अपमानित किया है। भाजपा महिला हितैषी होने का सिर्फ ढोंग रचती है, विपक्षी दल पूरी तरह से महिला शक्ति का विरोधी है। भाजपा चुनावों में वोट लेने के अलावा महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती।

नेगी व पठानिया ने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग के जरिये महिलाआ. ं को 1500 रुपये देने पर जो रोक लगवाई है, अगर वह नहीं हटती है तो जून में सरकार तीन महीने की राशि एक साथ पात्र महिलाओं को देगी। मुख्यमंत्री सुक्खू का बीते दिनों नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में दिया गया यह बयान स्वागत योग्य है। भाजपा 1500 रुपये का जितना मर्जी विरोध कर ले, यह राशि अप्रैल 2024 से महिलाओं को मिलकर रहेगी। लाहौल व स्पीति जिला की महिलाओं के खाते में योजना की पहली मासिक किश्त पहुंच चुकी है। प्रदेश के अन्य जिलों की महिलाओं को भी पहली अप्रैल 2024 से इस योजना का लाभ मिलना था। सरकार ने कैबिनेट बैठक में योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर कर दिया है। योजना को पहली अप्रैल से लागू करने की अधिस. चना तक जारी हो चुकी है। बावजूद इसके भाजपा ने चुनाव आयोग पहुंचकर योजना पर रोक लगवाई।

नेगी व पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जयराम ठाकुर पहले रोजाना यह कहते थे कि महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी कांग्रेस सरकार पूरी नहीं कर रही, लेकिन सरकार ने जब यह राशि देने के लिए चुनाव आचार संहिता से पहले फार्म भरवाना शुरू किए तो चुनाव की घोषणा होते ही जयराम योजना पर रोक लगवाने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गए। जिससे भाजपा व जयराम ठाकुर का दोगला चेहरा जनता के सामने बेनक. ाब हो चुका है।

उन्होंने कहा कि महिला शक्ति चुनावा. ं में भाजपा को कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है।

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के जीवन मे बड़ा परिवर्तन लाएगी। उन्हें 18000 रुपये सालाना मिलेंगे, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

प्रदेश में उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हिमाचल दिवस

vkdlk f'keyk A प्रदेश में 77वां हिमाचल दिवस हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर परेड कमांडर, आईपीएस अभिषेक के नेतृत्व में राज्य पुलिस, होमगार्ड, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स तथा एनसीसी कैडेटों की टुकडियों द्वारा भव्य मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह खूबसूरत राज्य 15 अप्रैल, 1948 को 30 छोटी–बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ अस्तित्व में आया था। राज्य की समृद्ध संस्कृति, उच्च परम्पराएं और असीम प्राकृतिक सौंदर्य, देवभूमि की विशिष्ट पहचान है। राज्य की वास्तविक शक्ति यहां के ईमानदार, कर्मठ और विकासशील लोग हैं तथा यहां शांतिपूर्ण वातावरण व सामाजिक सौहार्द है, जो इस पहाड़ी राज्य को दूसरों से अलग बनाता है।

राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के अस्तित्व में आने के बाद इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश ने तेजी से विकास का सफर तय किया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, दुर्गम क्षेत्र और अन्य जटिलताएं भी यहां के मेहनतकश लोगों के साहस को कम नहीं कर पाईं। प्रदेशवासियों ने राज्य को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो दूसरों के लिए एक उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों से विकास के सफर की शुरुआत करने के बाद आज हिमाचल देश भर में पहाड़ी राज्यों के विकास का आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। इसका श्रेय यहां के ईमानदार लोगों को जाता है जिन्होंने अपनी निष्ठा और लग्न से प्रदेश को विकास के इस आयाम तक पहुंचाया है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेशवासी भविष्य में भी इसी उत्साह के साथ राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखने में सदैव प्रयासरत रहेंगे।

श्री शुक्ल ने कहा कि युवा ही राष्ट्र की असली संपत्ति हैं, जो देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थिति समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हमें मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए, शिक्षण संस्थान, समाज के सभी वर्ग और युवाओं को जोड़कर एक प्रभावी संदेश देना होगा ताकि उनकी ऊर्जा व सामर्थ्य का राष्ट्र निर्माण में सदुपयोग हो सके। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे इस सामाजिक बुराई के खिलाफ मजबूती से पहल करें और प्रदेश को और सशक्त बनाने में योगदान दें।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने प्रदेश के उन महान सपूतों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। उन्होंने राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री शुक्ल ने सभी नागरिकों से आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने मता. धिकार का प्रयोग करने की अपील भी की।

उन्होंने विश्वास जताया कि वे भारत के संविधान के आदर्शों और मूल्यों को मजबूत करने के लिए अपने मताधिक. ार का प्रयोग करेंगे।

इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री (कर्नल) धनी राम शांडिल, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिद. ेशक संजय कुण्डू, प्रधान सचिव, सचिव सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जयराम ठाकुर कांग्रेस फोबिया से ग्रसित हो चुके है : कर्नल धनी राम शांडिल

vkdlk f'keykA स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कांग्रेस फोबिया से ग्रसित हैं। उन्हें नींद में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। कांग्रेस सरकार 15 महीने के कार्यकाल में 10 में से 5 गारंटियां पूरी कर चुकी है, नेता प्रतिपक्ष को वे क्यों नजर नहीं आ रही। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं होता, अच्छे कामों की सराहना भी विपक्षी दल को करनी चाहिए।

शांडिल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की याद्दाश्त भी कमजोर है। वह यह कैसे भूल गए कि ओपीएस मांगने पर उनकी सरकार ने कर्मचारियों पर लाठियां और वाटर कैनन चलवाई थीं। जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कहा था कि अगर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन चाहिए तो नौकरी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लें। नेता प्रतिपक्ष किस मुंह से कह रहे हैं कि उन्होंने ओपीएस का विरोध नहीं किया। अगर जयराम कर्मचारियों के हितैषी हैं तो एनपीएस के अंशदान के 9000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से वापस दिलाने में मदद करें। नेता प्रतिपक्ष घडियाली आंसू न बहाएं, जनता जान चुकी है कि वोट के जरिये चुनी सरकार को नोटों के दम पर गिराने का प्रयास किसने किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर का गणित वास्तव में ही कमजा. ं र है। 68 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक थे और तीन निर्दलीयों का समर्थन था। तब भी सरकार के पास पूर्ण बहुमत था, अब 62 विधायक विधानसभा में होने होने पर कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं, और सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। फिर जयराम कैसे कह रहे हैं कि सरकार को सत्ता में रहने का अधिक. ार नहीं। विपक्षी दल भाजपा को जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उसने राज्यसभा की एक सीट खरीद फरोख्त कर जीती। भाजपा के चेहरे का नकाब जनता के सामने उठ चुका है। शांडिल ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा बजट के बाद हुई, उसे कैबिनेट मंजूरी देकर 800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी कर दिया गया। योजना की अधिसूचना जारी हो चुकी है।

लाहौल व स्पीति में तो महिलाओं के खाते में पहली किश्त भी आ चुकी। जब योजना चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले से चल रही है तो भाजपा व नेता प्रतिपक्ष उसे क्यों रुकवाना चाह रहे हैं। जयराम महिलाओं को बताएं कि वह क्यों नहीं चाहते कि योजना जारी रहे।

जयराम ठाकुर ने तो अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं अब कांग्रेस सरकार सुख आश्रय योजना, युवाओं के लिए 680 करोड़ की स्टार्ट योजना, दूध पर एमएसपी, मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 60 रुपये की एकमुश्त वृद्धि के साथ बजट में अनेक जनहितैषी योजनाएं लाई है तो भाजपा को अपनी राजनी. तिक जमीन खिसकती दिख रही है।

सरकार की 1500 रुपये देने की नीयत ही नहीं : सुधीर शर्मा

vkdlk f'keykA धर्मशाला से बीज. पी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है।

सुधीर शर्मा ने कहा कि श्आप सभी जानते हैं पिछले कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी ने एक पत्रकार वार्ता करी जिसमें कि प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मौजूद थे और एक बयान निकल कर आया कि 1,500 जो महिलाओं को देने हैं हर महीने उसके ऊपर हम कानून लाएंगे।

सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि प्रदेश की माताओं बहनों को चुनावों से पहले जो गारंटी दी गई थी, 10 गारंटी में से एक गारंटी थी कि हर महिला को प्रदेश में 1,500 प्रति महीना देंगे। प्रदेश की पहली कैबिनेट होगी, उसमें निर्णय हो जाएगा और पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और एक फार्म जो हैं वह इलेक्शन के समय में भरवाया गया। उसके बाद अब दूसरा फार्म आ गया है और उसके ऊपर शर्तें इतनी लिख दी गई हैं कि मुझे लगता नहीं कि उसमें पात्र महिलाएं जो हैं उनकी संख्या को कम से कम करने का प्रयास जो है वह सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने किया है। मतलब देने की नीयत नहीं है, सिर्फ बखान करना है और इसी चीज को बार बार तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं।

1500 रुपये ऐसे दे रहे हैं जैसे भीख दे रहे हों

सुधीर शर्मा ने कहा कि बड़ी चालाकी के साथ मंथन करके पता किया गया कि सबसे कम महिलाओं की संख्या कहां लाहौल स्पीति में। वहां से शुरू करते हैं तो इस तरह से प्रदेश में जो है वो महिलाओं को बरगलाने का प्रयास, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए था कि जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है, मोदी जी की गारंटी है कि प्रदेश में और देश भर में जो महिलाएं हैं उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं उनके माध्यम से उनको चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो और रिटेल का क्षेत्र हो, उसके अंदर जो है वह सेल्फ हेल्प ग्रुप को उनको बढ़ावा दिया जाएगा और उनको उसमें सम्मिलित करके उसमें आगे बढ़ने का जो है वह न्योता दिया जाएगा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

सुधीर शर्मा ने कहा कि मोदी जी की गारंटी है कि जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कोई भी उत्पाद बना रहे हैं, उनकी मार्केटिंग जो है वह सरकार करेगी, केंद्र उसको सुनिश्चित करेगा और देशभर में जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको न केवल उन उत्पादों को बनाने के लिए उनका जो है वो बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए, सारी की सारी सहायता जो है वह सरकार जो है वह करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार। उससे क्या होगा कि जितनी हमारी महिलाएं हैं माताएं बहनें उनको एक आय का सूत्र पैदा होगा और 1,500 एक तरह से ऐसा देना है जैसे कि भीख दे रहे हैं, लेकिन जब आप उनको अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। कम से कम चार 5000 महीने की आय कमा सकती हैं, वो पैसा अपने खून पसीने का होगा, अपना होगा, इज्जत का पैसा होगा।

कांग्रेस के पास आंकड़ा ही नहीं, बस बरगलाने का प्रयास

सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सुक्खू जी से कि हमें 1500 1,500 दे दो। कोई मांगने नहीं गया तो खुद की घोषणा थी और ऐसी घोषणाएं करनी ही नहीं चाहिए थी वोट लेने के लिए। आज वर्तमान में जो सरकार कांग्रेस की है, अल्पमत में है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं आज मैंने बयान पढ़ा कि हम तो कानून ही बना देंगे, आपके पास आंकड़ा होगा तब कानून बनता है तो इन चीजों से बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है।

खजाना खाली है तो देंगे कहां से

सुधीर शर्मा ने कहा कि मोदी जी की गारंटी है सौर घर योजना आएगी। बिजली का बिल जीरो करेंगे और उससे क्या होगा। जो पैसा बचेगा वह परिवार के काम आएगा। लोगों में खुशहाली बढ़ेगी। समृद्धि परिवार में आएगी, समाज में आएगी यह सोच जो है।

यह भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सोच है, उनकी गारंटी है और यह पूरा होगी।

सुक्खू जी की सरकार की तरह नहीं है। कहेंगे कुछ करेंगे, कुछ। बोएंगे बबूल का बीज और निकलेगा उसमें से सोचेंगे कि आम निकल जाए तो कहां से होगा फल।

इस तरह की सोच जो है प्रदेश को खोखला कर रही है। आय के साधन जो है वह लोगों के खत्म होते जा रहे हैं। फिर कहते हैं खजाना खाली है। जब खजाना ही खाली है तो देंगे कहां से? या तो यह कह दें कि खजाना भरा हुआ तो दे दूंगा। इस तरह से प्रदेश की भोली भाली जनता को बरगलाने का प्रयास और यह सबसे ज्यादा कमजोर हाथों में पहली बार प्रदेश की सत्ता आई है।

हिमाचल की भ्रष्ट और पंगु सरकार को बदलना है

सुधीर शर्मा ने कहा कि हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग मिलजुल कर जहां देश में मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए सशक्त कार्यकाल के लिए दिन रात एक करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, वहीं प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को पंगु सरकार को हमको बदलना है और एक एक वोट जो है। छह के छह उपचुनाव हैं, नौ होंगे, नौ के नौ उपचुनाव जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। जहां देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वहीं प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी और जो गारंटी मोदी जी ने दी है उनको पूरा करने के लिए जो है वह संकल्पित रहकर के सरकार काम करेगी, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

पांच सालों में बना लेंगे 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी : अनुराग ठाकुर

vkdlk mukA केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने नारी शक्ति का वंदन भी किया और नारी शक्ति वंदन बिल लाकर उनको 33 परसेंट आरक्षण दिया। और जब पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राज्य में तो धूमल जी ने 50 परसेंट आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में दिया था। हमने अपने संगठन में 25 परसेंट आरक्षण महिलाओं को दिया।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा यही नहीं रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा बिल्कुल मुत में 10 करोड़ बहनों को दिया।

12 करोड़ शौचालय इज्जत घर के रूप में बनाकर बहनों को दिए। 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी। 4 करोड़ के लगभग पक्के मकान बनाए, जिनमें से 3 करोड़ से ज्यादा सीधे बहनों के नाम पर है। मुत में इलाज और मुत में अनाज पांच साल दिया।

अगले पांच साल और भी देंगे। इसके अलावा चाहे मुत में गर्भवती महिला का इलाज हो, दवाई हो, उपचार हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो और अब लखपति दीदी बनाने का अभियान।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया है। अगले पांच सालों में लखपति दीदी 2 करोड़ बहनों को और बना लेंगे। हम लोग करने में विश्वास करते हैं। कांग्रेस के लोग रुकवाने में विश्वास करते हैं। उनकी सरकार बनी थी तो पहली कैबिनेट में उनको निर्णय करना था। पहली कैबिनेट के बाद देश की प्रदेश की 30 लाख बहनों को 1,500 महीना मिलना था। मेरा सवाल केवल कांग्रेस से इतना है आज हिमाचल प्रदेश की 30 लाख बहनों में से कितनी लाख बहनों को 1,500 मिल रहे हैं? इसका जवाब उनको देना होगा। किसने रोका था। पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 40 विधायक थे। तीन इंडिपेंडेंट का भी सहयोग था और 1500 रुपये देने में तो भाजपा का भी सहयोग था भाई क्यों नहीं किया?

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मां चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैंने मां चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन किए और मां चिंतपूर्णी का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला।

अनुराग ठाकुर ने कहा देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मां चिंतपूर्णी के दरबार में हर कोई हाजिरी लगाने आता है, आशीर्वाद लेने आता है और आज पूरे देशभर में राम नवमी को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज ही मुझे मां चिंतपूर्णी के दर्शन और आशीर्वाद लेने का अवसर मिला।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा देशभर में जिस तरह से लोगों में आज की विशेष तौर पर युवा पीढ़ी में धर्म के प्रति जागरुकता आई है और जो समर्पण भाव है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो विकास से विरासत, क्योंकि विकास जो देश का हुआ वो तो हुआ ही साथ ही साथ सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक हो या अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। ये सब पिछले कुछ वर्षों में हुआ और इससे हमारी विरासत को बचाने का और आगे बढ़ाने का काम हुआ है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा हम सौभाग्यशाली हैं हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनका धर्म में विश्वास भी है। सब धर्मों का सम्मान भी करते हैं। सबका साथ सबका विकास भी करते हैं। दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज देश के अलग अलग कोनों में आ रहे हैं।

इससे टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है और हमारे यहां पर रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं तो विकास भी, विरासत भी।

हम देखते हैं करोड़ों लोग प्रतिवर्ष श्रद्धालु के रूप में आते हैं तो हिमाचल में एक बहुत बड़ी पर्यटन की भूमिका है।

युवाओं के साथ बड़ा धोखा अग्निवीर योजना : कांग्रेस

vkdlk f'keykA कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार और स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी पठानिया ने कहा है कि अग्निवीर योजना युवाओं के साथ बड़ा भद्दा मजाक और सरासर धोखा है। आम सैनिक और अग्निवीर के बीच काफी भेदभाव किया जा रहा है। अग्निवीर को शहीद का दर्जा न होने से युवाओं में केंद्र सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। अब युवा सेना में जाने के लिए उत्साहित नहीं हैं। युवाओं का सेना के प्रति क्रेज घट गया है।

चंद्र कुमार व पठानिया ने कहा कि युवा अब सेना में अपना भविष्य सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सेना की भर्ती के लिए पहले युवा दिन–रात मेहनत करते थे। सुबह और शाम के समय सड़कों के किनारे और खेल मैदानों में युवाओं को दौड़ लगाते और अभ्यास करते हुए देखा जाता था। अब इक्का–दुक्का युवा ही दिखते हैं। भर्ती होने के बाद अग्निवीर के साथ पक्षपात हो रहा है, उन्हें आम सैनिकों के साथ नहीं रखा जाता, ना ही घुलने–मिलने देते हैं। उन्हें अलग बैरक में रखा जा रहा है, इससे अग्निवीर हतोत्साहित हैं।

कृषि मंत्री और स्टेट प्लानिंग बोर्ड उपाध्यक्ष ने कहा कि देश की सेवा करते वीरगति को प्राप्त होने पर अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा। न ही परिजन को एक्स सर्विसमैन और कैंटीन के लाभ मिल पा रहे। अग्निवीर के परिवार को सिर्फ एक करोड़ रुपये ही मिलेंगे, जबकि आम सैनिक के साथ ऐसा नहीं है। शहीद के दर्जे के साथ सैनिक के परिवार को आर्थिक सहायता भी ज्यादा है, 15 साल की सेवा पूरी होने तक परिवार को पूरा वेतन और अनेक सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसदों को युवाओं को यह बताना चाहिए कि उनके भविष्य के साथ यह खिलवाड़ क्यों किया गया है। हिमाचल प्रदेश से हज़ारों युवा सेना में भर्ती होते थे, कांगड़ा, हमीरपुर व मंडी जिला में तो हजारों सैनिक परिवार हैं, लेकिन अग्निवीर योजना लागू होने पर भाजपा सांसदों ने युवाओं की आवाज को संसद में एक बार भी नहीं उठाया। उन्होंने चुप्पी साधे रखी। वे युवाओं का साथ देने के बजाय अग्निवीर योजना के फायदे गिनाते रहे। चंद्र कुमार व भवानी ने कहा, भाजपा को युवाओं को जवाब देना होगा कि सेना में युवाओं के लिए नौकरी के दरवाजे बंद क्यों किए गए। शहीद का दर्जा देने में भेदभाव क्यों हो रहा है। क्योंकि, युवाओं और उनके परिवारों में अग्निवीर योजना को लेकर खासा रोष है।

महिला सम्मान योजना पात्र महिलाओं को जून में मिलेंगे 3000 रुपये : सुक्खू

vkdlk f'keykA मंगलवार दोपहर बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जून में प्रदेश की पात्र महिलाओं को महिला सम्मान निधि के तहत 3000 एक साथ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना जब चुनाव के दौरान जारी रह सकती है तो प्रदेश की महिला

फॉर्म संबंधित विभाग को दें, नहीं तो कांग्रेस विधायक के पास

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस संदर्भ में मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से चुनाव आयोग को अवगत कराया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए अपने फार्म संबंधित विभाग को दे सकती हैं. अगर विभागीय अधिकारी फॉर्म नहीं लेते हैं तो संबंधित क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों के पास इन फॉर्म को जमा करवाया जाए।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होते ही महिलाओं को एक साथ सभी माह के पैसे जारी किए जाएंगे।

कांग्रेस सरकार पूरी तरह स्थिर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता बिकाऊ विधायकों को वोट की चोट से सबक सिखाएगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने पैसे के दम पर सत्ता को हथियाना का षड्यंत्र रचा. जिसमें वह फेल हो गए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से स्थिर है. कांग्रेस पार्टी लोकसभा की चारों सीटों सहित विधानसभा के छह उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी।

पुरानी पेंशन को लेकर बनेगा कानून

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है।

अभी इस योजना को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विधानसभा में इस संदर्भ में कानून बनाया जाएगा। कानून के बनने से इस योजना को बंद नहीं किया जा सकेगा।

पहले प्रयास में पास की यूपीएससी परीक्षा सफाई ठेकेदार की बेटी ने

vkdlk eMh A हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की बल्ह घाटी के रत्ती गांव की बेटी तरुणा कमल ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले और उपमंडल का मान बढ़ाया है। रत्ती में सफाई ठेकेदार अनिल के घर पैदा हुई तरुणा ने पहले की प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 203वां रैंक हासिल किया है। तरुणा ने मॉडर्न पब्लिक स्कूल रत्ती से 12वीं की परीक्षा पास करने की। इसके बाद चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी पालमपुर से वेटरनरी डॉक्टर की परीक्षा पास की है। तरुणा वेटरनरी की पढ़ाई के बाद चंडीगढ़ में यूपीएससी की कोचिंग ले रही थीं। तरुणा ने बताया कि सफलता का एकमात्र रास्ता परिश्रम है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है।

फंदे पर झूला बेटी के भागने की खबर सुनते ही परेशान पिता, पत्नी से कहा–मैं ताने नहीं सह पाऊंगा

txjko ¼i¡tkc½A जगरांव के गांव बरसाल में एक युवक लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया। इसका पता चलते ही पिता ने घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी लड़के की बहन व जीजा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस ने आरोपी लड़के समेत मां, बहन व जीजा पर थाना सदर में मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों की पहचान जश्नप्रीत सिंह, ऊषा रानी निवासी गांव बरसाल, सनमप्रीत कौर उर्फ सिम्मी व मनोहर सिंह निवासी तुगल के रूप में हुई है।

चौकीमान चौकी के इंचार्ज रणधीर सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी ने बताया कि उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में कॉल सेंटर में नौकरी करती है। आरा. `पी वहीं सुरक्षागार्ड है।

दो दिन पहले उनकी बेटी काम पर गई। लेकिन शाम को घर वापस नहीं आई। जब उन्होंने लड़की की तलाश शुरू की तो पता चला कि उनकी बेटी तीन बजे काम से छुट्टी लेकर चली गई जिसके बाद पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने अपने स्तर पर पता करने की बात कही।

इसी दौरान उन्हें पता चला कि आरा. `पी लड़का भी अपने घर पर नही है जिसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि आरोपी ही अपनी मां बहन व जीजा के साथ मिलकर उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया। इस दौरान बेटी की तलाश में अपने देवर के घर चली गई। जबकि उसका पति गांव बरसाल में अकेला था। इस दौरान उसके पति का फोन आया कि वह आत्महत्या करने लगा है। वह लोगों के ताने नहीं सुन सकता। अपने पति का फोन सुनकर वह तुरंत देवर के साथ अपने घर गांव बरसाल पहुंची। वहां देखा तो उसके पति ने चुनरी से फंदा लगा लिया था। वे उसे लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने महिला के बयानों पर आरोपी लड़के, उसकी मां, बहन व जीजा पर मामला दर्ज कर लिया। चारों आरोपी अभी फरार हैं जिनको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन सूत्रों की मानें तो देर शाम को पुलिस ने आरोपी लड़के की बहन व जीजा को हिरासत में ले लिया जिनसे पुलिस लड़की के बारे में पूछताछ कर रही है।

हिसार में चौटाला परिवार के सदस्य आमने–सामने लड़ेंगे चुनाव

fglkj ¼gfj;k.kk½A लोकसभा चुनाव में हिसार की सीट पर रोचक मुकाबला होगा। चुनावी मैदान में सगे चाचा ससुर और बहू एक–दूसरे को टक्कर देंगे। भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह के सामने जजपा ने बाढड़ा की विधायक नैना चौटाला को उतार दिया है। यह पहला मौका होगा जब लोकसभा चुनाव में चौटाला परिवार के सदस्य आमने–सामने लड़ेंगे। वहीं इनेलो की ओर से सुनैना चौटाला के मैदान में आने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो हिसार के रण में चौटाला बनाम चौटाला बनाम चौटाला होगा।

हिसार लोकसभा सीट पर पूर्व उपप्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का परिवार टकराएगा। भाजपा ने चौधरी देवीलाल के बेटे 78 वर्षीय रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है। जजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला को मैदान में उतार दिया है।

पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां और जजपा की बाढड़ा से विधायक नैना चौटाला अपने चाचा ससुर को टक्कर देंगी। बता दें कि नैना चौटाला का मायका आदमपुर के गांव दड़ौली में है।

वहीं, सुनैना चौटाला का मायका हिसार जिले के उकलाना के दौलतपुर गांव में है।

आक्रोश नहीं झेलना चाहते दुष्यंत

इस समय किसान जजपा के प्रति आक्रोशित हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला उनके आक्रोश का शिकार नहीं बनना चाहते हैं। राजनीति में लंबे भविष्य को देखते हुए दुष्यंत ने इस लोकसभा चुनाव के बजाय विधानसभा चुनाव पर फोकस शुरू कर दिया है।

नैना चौटाला को इसलिए उतारा

हिसार लोकसभा सीट पर दुष्यंत चौटाला 2014 में इनेलो के टिकट से सांसद बन चुके हैं। 2019 के बाद वह जजपा के प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव मैदान में उतरे थे। वे पिछली दस साल की मेहनत से तैयार सियासी जमीन को छोड़ना नहीं चाहते। इस कारण उन्होंने परिवार के सदस्य को यहां उतार कर अपनी मजबूत दावेदारी दिखाने का प्रयास किया है। जजपा के हिसार के तीन विधायकों में से दो बागी हो चुके हैं। ऐसे में हिसार लोकसभा सीट पर नैना चौटाला से मजबूत कोई चेहरा जजपा में नजर नहीं आ रहा था।

पहले भी आमने–सामने रहा चौटाला परिवार

वर्ष 2000 के चुनाव में रोड़ी विधानसभा सीट से ओमप्रकाश चौटाला इनेलो और रणजीत सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर आमने–सामने रहे। इस चुनाव में ओमप्रकाश चौटाला जीते थे। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में डबवाली सीट पर इनेलो के अजय सिंह चौटाला के सामने उनके चचेरे भाई रवि चौटाला निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आमने–सामने लड़े, जिसमें अजय सिंह चौटाला जीते थे।

कांग्रेस से बृजेंद्र या जेपी उतरे तो चारों प्रमुख दलों के प्रत्याशी होंगे जाट

हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी, पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन के नाम सबसे अधिक चर्चा में हैं। अगर बृजेंद्र सिंह या जेपी चुनावी मैदान में आए तो चारों प्रमुख दलों के प्रत्याशी जाट होंगे। अगर चंद्रमोहन सामने आए तो वह बिश्नोई प्रत्याशी होंगे।

उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस इसी सप्ताह अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। पिछले दिनों नलवा विधानसभा की एक रैली में पूर्व सीएम की ओर से बिना नाम लिए चौधरी भजन लाल पर की गई टिप्पणी और हिसार से कुलदीप को टिकट नहीं दिए जाने से भाजपा के खिलाफ उपजी नाराजगी का लाभ लेने का प्रयास कांग्रेस कर सकती है।

पति–पत्नी के नाम है अनोखा रिकॉर्ड अखिलेश–डिंपल दोनों ने उपचुनाव से शुरू की सियासी पारी

dUukSt A अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव की गवाह रही इत्रनगरी दो बार उपचुनाव की प्रक्रिया से भी गुजरी है। दोनों ही उपचुनाव सपा सांसदों के इस्तीफे के बाद हुए। खास बात यह रही कि दोनों ही बार सपा के ही सांसद निर्वाचित हुए। पहली बार हुए उपचुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहां से पहली बार सांसद बने। दूसरी बार हुए उपचुनाव में पत्नी डिंपल यादव यहां से निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुईं।

कन्नौज संसदीय सीट पर हुए 16 चुनावों के दौरान सात बार समा. जवादी पार्टी का कब्जा रहा है। वर्ष 1998–2014 के बीच हुए सभी चुनाव में सपा को लगातार कामयाबी मिलती रही है। वर्ष 2019 में भाजपा की जीत के बाद यह सिलसिला टूटा। पहली बार उपचुनाव वर्ष 2000 में तब हुआ, जब 1999 में यहां से सांसद बने मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दिया था। तब मुलायम सिंह यादव कन्नौज के साथ ही संभल से भी लड़े थे। दोनों जगह जीत मिलने पर उन्होंने कन्नौज सीट से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा से खाली हुई सीट पर अखिलेश यादव पहली बार सियासत के मैदान में आए। जनता के दरबार में हाजिरी लगाकर वह दिल्ली तक पहुंचने में कामयाब भी हुए। उसके बाद वह लगातार तीन बार सांसद बने। वर्ष 2009 में वह तीसरी बार सांसद बने। उसके तीन साल बाद वर्ष 2012 में सूबे की सपा की सरकार बनी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। ऐसी सूरत में उन्हें इस सीट से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी खाली हुई सीट पर पत्नी डिंपल यादव यहां से उम्मीदवार बनीं।

उस चुनाव में वह निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुईं। यह इस सीट पर एक रिकॉर्ड है।

चार बार लोकसभा चुनाव लड़े अखिलेश, हर बार जीते

अखिलेश यादव अब तक चार बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कन्नौज में उन्होंने वर्ष 2000, 2004 और 2009 में ताल ठोकी और कामयाब भी हुए। वर्ष 2012 से 2017 तक सूबे का मुख्यमंत्री रहने के दौरान वह लोकसभा चुनाव से दूर रहे। 2019 में उन्होंने आजमगढ़ संसदीय सीट से किस्मत आजमाई और वहां भी जीत हासिल की।

तीन सीट से चुनाव लड़ीं डिंपल, हर बार उपचुनाव से इंट्री

इस समय मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव अब तक तीन बार चुनाव जीत चुकी हैं। एक खास बात यह है कि उन्होंने तीन सीट से किस्मत आजमाई है। तीनों ही बार नई सीट पर उनकी इंट्री उपचुनाव से हुई है। पहली बार फिरोजाबाद, उसके बाद कन्नौज और अब मैनपुरी से मैदान में हैं।

पति–पत्नी दोनों के नाम अनोखा रिकॉर्ड

– अखिलेश यादव लगातार तीन चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने वाले इकलौते सांसद हैं।

– डिंपल यादव निर्विरोध ही निर्वाचित होने वाली इकलौती सांसद हैं।

महिला के साथ वकील के केबिन में दुष्कर्म, बेटी की पढ़ाई के लिए लोन की फाइल भरने के बहाने बुलाया था

pMhx<A मोगा की रहने वाली एक महिला के साथ जगरांव के कोर्ट परिसर में एडवोकेट के केबिन में एक फाइनेंसर ने दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरतार कर थाना सिटी में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान परमिंदरपाल सिंह गरेवाल निवासी गांव बरसाल के रूप में हुई है।

आरोपी ने शराब के नशे में महिला के साथ रेप किया। आरोपी ने महिला को उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले लोन की फाइल भरने के लिए ही मोगा से जगरांव बुलाया था। लेकिन दुष्कर्म कर उसे भगा दिया।

30 मार्च की घटना के बाद महिला ने 02 अप्रैल को पुलिस में शिकायत सौंपी। इस मामले में जांच के बाद आरोपी फाइनेंसर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

महिला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह जगरांव में सुखबीर सिंह नाम के व्यक्ति को जानती थी। जो उसका मुंह बोला भाई बना हुआ है। उसकी 13 साल की बेटी पांचवीं पास है। उसको आगे पढ़ने के लिए स्कूल के दाखिले के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसने अपने मुंह बोले भाई से किसी से ब्याज पर पैसे दिलाने को कहा था।

सुखबीर ने बताया कि उसकी फाइनेंसर से पूरी बात हो गई है। वह पैसे ब्याज पर दे देगा। जिसके चलते वह 30 मार्च को देर शाम को मोगा से जगरांव आ गई। इस दौरान जब फाइनेंसर को फोन किया। तो उसने कहा कि वह कोर्ट परिसर में एडवोकेट के केबिन में आ जाए। वह 248 नंबर केबिन में चले गए। वहा पर एडवोकेट कपिल और आरोपी बैठे शराब पी रहे थे। जब वह केबिन में पहुंची तो उसे बिठा कर इंतजार करने को कहा गया। इसी दौरान सुखबीर को फोन आ गया और एडवोकेट कपिल आरा. `पी फाइनेंसर को यह कह कर चला गया कि वह घर जा रहा है। वह जाते समय केबिन बंद कर जाना। एडवोकेट कपिल के जाने के बाद शराब के नशे में आरोपी फाइनेंसर ने उसको अंदर बुला कर केबिन की कुंडी लगा ली। जिसके बाद उसके जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। आरा. `पी ने उसका रेप किया। कुछ समय बाद उसका मुंह बोला भाई आया और मोगा में उसके घर छोड़ कर आया। उसने वारदात के दो दिन बाद पुलिस को शिकायत दी।

शिक्षा बोर्ड हरियाणा में अब साल में दो बार होगी फाइनल परीक्षा

fHkokuh ¼gfj;k.kk½A हरियाणा शिक्षा बोर्ड मार्च–अप्रैल में हुई बारहवीं की परीक्षा का परिणाम 15 मई से पहले घोषित करने की तैयारी कर रहा है। बारहवीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य भी अंतिम चरण में हैं, जो दस दिन में पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं मार्च–अप्रैल 2024 में दसवीं की परीक्षा से असंतुष्ट परीक्षार्थी जून–जुलाई में फिर से परीक्षा देकर बेहतर अंक हासिल कर सकेंगे। इसके लिए बोर्ड सेम पैटर्न पर जून–जुलाई में भी फिर से दसवीं की पूरे सिलेबस के साथ परीक्षा आयोजित कराएगा।

हरियाणा के सिरसा में डेरों का प्रभाव... हर कोई चाहता है आशीर्वाद

fljlk A सिरसा के सरसाईनाथ की नगरी सिरसा में लोगों का अलग–अलग डेरों व धार्मिक स्थलों के प्रति विशेष झुकाव है। यही कारण है कि चुनावों के दिनों में इन जगहों पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। देश–प्रदेश के बड़े–बड़े नेता यहां आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन डेरों का आशीर्वाद जिसे मिलता है, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है क्योंकि इनसे अलग–अलग समुदाय के लोग जुड़े हैं। प्रदेश की पुरानी राजनीतिक गतिविधियों पर गौर किया जाए तो दिग्गजों से लेकर हर प्रत्याशी यहां से आशीर्वाद लेता नजर आया है।

बीती 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सिरसा हवाई अड्डे से सीधे ग्राम बाबा संघर साधा मुख्य डेरा बाबा भूमणशाह पहुंचे थे। वह पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं जो आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। इससे पहले भी बड़े–बड़े राजनेता डेरा प्रमुखों से मुलाकात करते और आशीर्वाद लेते नजर आए हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के जेल जाने से पहले तक देश के दिग्गज नेता डेरे में आशीर्वाद के लिए आते थे।

सिख समुदाय का दिखता है विशेष असर

सिरसा जिले में सिख समुदाय का बड़ा वोट बैंक है जो प्रत्याशी की जीत और हार में अहम भूमिका निभाता है। पंजाब की सीमाओं से लगा होने के कारण पड़ोसी राज्य की राजनीतिक हलचल का असर भी दिखता है। कालांवाली, डबवाली, रानियां, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, रतिया व टोहाना में बड़ी संख्या में सिख मतदाता हैं। नरवाना में भी सिखों का असर देखने को मिलता है।

सिरसा में मजहबी सिख और बाजीगर, जट्ट सिख, कंबोज मुख्य रूप से हैं। करीब 4.30 लाख सिख वोटर हैं। लोकसभा क्षेत्र के कुल वोट बैंक का यह 20 प्रतिशत के करीब है, इसलिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी वोट पर असर डालती है। इसके अतिरिक्त नामधारी पंथ से जुड़े नामधारी सिख भी हैं। ये दो गुटों में बंट गए हैं। एक गुट कांग्रेस समर्थक है और दूसरा अन्य पार्टियों को वोट डालता है।

डेरा सच्चा सौदा के लाखों अनुयायी

हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के लाखों अनुयायी हैं। यहां पर नियमित सत्संग होते हैं। सिरसा, करनाल, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, जींद, अंबा. ला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र ज़िले ऐसे हैं , जहां पर डेरा का बड़ा आधार है। राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो विधानसभा चुनावों में भी डेरे ने 22 सीटों पर प्रभाव डाला था। ऐसे में प्रदेश में सियासी हलचल पैदा करने में डेरे के वोट बैंक का बड़ा हाथ होता है।

डायबिटीज रोगियों में लिवर कैंसर का खतरा अधिक, इन लक्षणों से कर सकते हैं पहचान

कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, इस रोग को बहुत खतरनाक माना जाता है। हर साल दुनियाभर में लाखों लोग कैंसर का शिकार होते हैं और इसकी मृत्युदर भी काफी अधिक रही है। लिवर कैंसर भी वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा रहा है। अध्ययनकर्ताओं ने बताया लाइफस्टाइल की कुछ गड़बड़ आदतें लिवर की समस्याओं, यहां तक कि लिवर कैंसर का भी कारण बन सकती हैं।

लिवर कैंसर दुनियाभर कैंसर से होने वाली मौतों का तीसरा प्रमुख कारण है। साल 2020 में अनुमानित 8.30 लाख लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई।

लिवर से संबंधित वैश्विक समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक करने और इससे बचाव को लेकर शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लिवर में होने वाला कैंसर पिछले एक दशक में काफी तेजी से बढ़ा है, इससे बचाव को लेकर सभी लोगों को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।

लिवर में होने वाला कैंसर

लिवर कैंसर, लिवर की कोशिकाओं में शुरू होता है। लिवर कैंसर का सबसे आम प्रकार हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, जो मुख्य प्रकार की लिवर कोशिका (हेपेटोसाइट) में होता है।

अध्ययनकर्ताओं ने बताया, लिवर को. शिकाओं के डीएनए में परिवर्तन के कारण इसमें कैंसर हो सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस संक्रमण या लिवर में लंबे समय से बनी हुई कुछ प्रकार की बीमारियों के कारण भी कैंसर विकसित होने का खतरा रहता है। लेकिन कभी–कभी लिवर कैंसर उन लोगों में भी हो सकता है जिन्हें कोई अंतर्निहित बीमारी नहीं होती।

क्या है लिवर कैंसर की पहचान?

अधिकांश लोगों में प्राथमिक स्थिति में लिवर कैंसर के कोई संकेत या लक्षण नहीं होते हैं। आपको पाचन से संबंधित कुछ समस्याएं जरूर होती रह सकती है हालांकि जैसे–जैसे कैंसर कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं इसके लक्षण अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। बिना प्रयास के वजन कम होना, भूख न लगना, पेट में दर्द, मतली और उल्टी, कमजोरी और थकान बने रहना, पीलिया की समस्या बार–बार होते रहना भी लिवर कैंसर का शुरुआती संकेत माना जाता है।

किन लोगों में इसका खतरा अधिक

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं जिन लोगों को हेपेटाइटिस–बी या हेपेटाइटिस सी वायरस का दीर्घकालिक संक्रमण रहा है उनमें लिवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सिरोसिस जैसी बीमा. रियां भी इसके जोखिमों को बढ़ाने वाली हो सकती हैं। इसके अलावा बार–बार फैटी लिवर की समस्या होते रहना, शराब का सेवन भी आपको लिवर कैंसर का शिकार बना सकता है।

अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें और भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों में लिवर के कैंसर का खतरा समय के साथ बढ़ सकता है।

डायबिटीज रोगियों में कैंसर

अध्ययन से पता चलता है कि टाइप 1 और टाइप–2 दोनों प्रकार के डायबिटीज रोगियों में लिवर कैंसर विकसित होने का जोखिम अधिक हो सकता है। ऐसे लोगों में, बिना मधुमेह वाले लोगों की तुलना में कैंसर का खतरा दो से तीन गुना अधिक देखा गया है। यदि मधुमेह ठीक से नियंत्रित नहीं रहता है तो जोखिम और भी बढ़ जाता है। हाई ब्लड शुगर की स्थिति में शरीर में कोशिकाओं को ईंधन देने के लिए आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है। अतिरिक्त ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान हानिकारक रसायन और फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जिससे लिवर कोशिक. ाओं में कैंसर विकसित होने का जोखिम अधिक बढ़ सकता है।

अस्पतालों में फिर बढ़े चमकी बुखार के मामले, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित

चमकी बुखार (इंसेफेलाइटिस) के कारण हर साल बड़ी संख्या में बच्चे अस्पतालों में भर्ती होते हैं, इसके कारण मौत का खतरा भी अधिक देखा जाता रहा है। सरकार लगातार इस खतरनाक रोग से बचाव लेकर अभियान चला रही है, हालांकि अब भी ये बड़ा खतरा बना हुआ है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कुछ जिलों में एक बार फिर से चमकी बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। मुजफरपुर में करीब 14 लोगों में चमकी बुखार के लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालांकि रोगियों के जांच की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

रिपोर्टस के मुताबिक मुजफरपुर के पीआईसीयू में शनिवार–रविवार दोना. ं दिन 7–7 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चों की निगरानी कर रही है। खून के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों को बुखार से बचाव के उपाय करते रहने की सलाह दी है। आइए जानते हैं कि चमकी बुखार के क्या कारण हैं और बच्चों को इससे किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है?

उत्तर प्रदेश– बिहार में देखे जाते रहे है मामले

बिहार के कई राज्य इस गंभीर रोग के शिकार रहे हैं– मुजफरपुर उनमें से एक है। पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश–बिहार सहित कई राज्यों में इंसेफेलाइटिस के मामले स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए बड़ी चिंता का कारण रहे हैं। इंसेफेलाइटिस के मामले बैक्टीरियल या वायरल दोनों प्रकार के संक्रमण के कारण हो सकते हैं। इसके कारण ब्रेन इंलामेशन का खतरा बढ़ जाता है जिसके गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ये बीमारी वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकती है हालांकि बच्चों को इसका सबसे ज्यादा शिकार देखा जाता रहा है।

इंसेफेलाइटिस के क्या कारण हैं?

वायरल–बैक्टीरियल संक्रमण, ऑटोइम्यून इंलामेशन, कीड़ों के काटने या कुछ प्रकार की बीमारियों के कारण इंसेफेलाइटिस की समस्या हो सकती है इसमें ब्रेन में सूजन हो जाता है। इंसेफेलाइटिस के लगभग 70त्न मामले वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं, जिनमें छोटे बच्चे (एक वर्ष और उससे कम उम्र) और बुजुर्गों (65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के) के लोगों में खतरा सबसे ज्यादा देखा जाता रहा है।

वायरस से मुकाबले की स्थिति में मस्तिष्क में सूजन की समस्या हो सकती है। समय के साथ इस रोग के लक्षण बिगड़ते जाते हैं और कुछ स्थितियों में ये जानलेवा भी हो सकती है।

कैसे होते हैं इसके लक्षण?

इंसेफेलाइटिस आमतौर पर बुखार–सिरदर्द जैसे लक्षणों के साथ शुरू होता है। समय पर अगर इस समस्या पर ध्यान न दिया जाए या इलाज न किया जाए तो इसके कारण दौरे पडऩे, भ्रम, चेतना की हानि और यहां तक कि कोमा भी हो सकता है। इसके लक्षण समय के साथ गंभीर होते जाते हैं। इन स्थितियों में भयंकर सरदर्द, उल्टी–भ्रम होने, याददाश्त की समस्या, बोलने–सुनने की दिक्कत होने, बेहोशी की समस्या हो सकती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, इंसेफेलाइटिस से बचाव को लेकर सभी लोगों को सतर्कता बरतते रहने की आश्यकता होती है। विशेषतौर पर जिन शहरों में पहले से इसके मामले रिपोर्ट किए जाते रहे हैं वहां बच्चों की सेहत को लेकर सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है।

इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए क्या करें?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वायरल इंसेफेलाइटिस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका उन वायरस के संपर्क से बचना है जो इस बीमारी का कारण बन सकते हैं।

इसके लिए स्वच्छता का ध्यान रखना सबसे आवश्यक है। हाथों को साबुन और पानी से बार–बार और अच्छी तरह धोएं। कपड़े–बिस्तर को एक दूसरे से शेयर न करें। कुछ संक्रमित मच्छरों के काटने से भी इस रोग के होने का खतरा रहता है इसलिए आसपास की साफ–सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाना जरूरी है। अगर आपमें या बच्चे में इस रोग के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत अस्पताल जाएं।

फ्रूट–जूस से लेकर आइसक्रीम तक, सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं ये चीजें, रहें सावधान

अगर आप चाहते हैं कि सेहत ठीक रहे, क्रोनिक बीमारियों के खतरे से बचे रहें तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप खान–पान की चीजों को लेकर विशेष सावधानी बरतते रहें। हम जो कुछ भी खाते–पीते हैं उसका सीधा असर हमारी सेहत पर होता है। गर्मी के दिनों में ठंडक के एहसास के लिए आइसक्रीम खाना भी हमारी पहली पसंद में से एक रहा है, पर क्या आप जानते हैं कि असल में इससे सेहत को कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं?

इतना ही नहीं अगर आपको लगता है कि शरीर की पौष्टिकता की पूर्ति के लिए बाजार में मिलने वाले फ्रूट जूस लाभकारी हैं तो भी आपको सावधान हो जाने की जरूरत है।

पैक्ड फ्रूट जूस और आइसक्रीम को वजन बढऩे से लेकर डायबिटीज और कई अन्य प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण माना जाता रहा है। पैक्ड जूस को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए उसमें कई प्रकार रसायन और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जिससे सेहत को दीर्घकालिक तौर पर कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस तरह की चीजों से सभी लोगों को दूरी बनाने की सलाह क्यों देते हैं?

पैक्ड जूस को एक साल और उससे अधिक समय तक भी स्टोर किया जा सकता है। इन्हें लंबे समय तक ताजा रखने की प्रक्रिया के दौरान इसके जरूरी विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। यदि आप पैक किए गए जूस के इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो आपको इनमें ऐडेड शुगर के साथ–साथ स्वाद को ताजा रखने और जूस से कोई अप्रिय गंध न आए इससे बचाने के लिए कई प्रकार के रसायनों को मिलाया जाता है।

कई अध्ययनों में पाया गया है कि इस प्रकार के रसायन शरीर को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं।

मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमा. रियों का जोखिम

पैक्ड जूस में ऐडेड शुगर के कारण ये न केवल मीठे होते हैं, बल्कि घर पर बने ताजे जूस की तुलना में कैलोरी में भी अधिक होते हैं। ये कैलोरी शरीर में अतिरिक्त वजन को बढ़ाने वाली हो सकती है, यानी कि अगर आप अक्सर इन जूस का सेवन करते हैं तो समय के साथ बेली फैट और मोटापा बढऩे का खतरा हो सकता है।

पैक्ड जूस में कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा होती है जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकते हैं और लंबे समय में मधुमेह का कारण बन सकते हैं।

आइसक्रीम से बच्चों की सेहत को नुकसान

बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को आइसक्रीम पसंद होती है हालांकि कुछ शोध बताते हैं कि जो लोग अक्सर आइसक्रीम खाते हैं उनका कैलोरी इंटेक अधिक हो सकता है। बच्चों की सेहत पर इसके कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखे गए हैं।

आइसक्रीम में अक्सर चीनी और वसा की मात्रा अधिक होती है, जिससे वजन बढऩे का खतरा रहता है। इसके अलावा आइसक्रीम के कारण दांतों में झनझनाहट और कैविटी की समस्या बढऩे का भी खतरा देखा जाता है।

नमक की अधिकता बढ़ा रही है हार्ट की समस्याएं

हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ आमिर सिद्दिकी कहते हैं, नमक के अधिक सेवन का स्वास्थ्य समस्याओं पर सीधा असर पड़ता है। ये उच्च रक्तचाप का सबसे बड़ा कारक है जिससे धमनियों की दीवारों पर अतिरिक्त दवाब बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढऩे के कारण दिल का दौरा, स्ट्रोक और अन्य हृदय रोगों का खतरा बढ़ रहा है।

गड़बड़ लाइफस्टाइल के कारण हार्ट की दिक्कतें पहले से बढ़ी हुई देखी जा रही हैं, नमक का सेवन इस खतरे को और भी बढ़ा देता है। हर उम्र के व्यक्तियों में नमक के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव देखे जाते रहे हैं। इसके जोखिम सिर्फ हृदय रोगों तक भी सीमित नहीं हैं।

नमक से होने और समस्याएं

डॉक्टर ने कहा कि अधिक नमक के सेवन से किडनी की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। हमारी किडनी शरीर के सोडियम संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। जो लोग अधिक नमक खाते हैं उनकी किडनी इसे ठीक तरीके से बाहर नहीं कर पाती है जिससे किडनी से संबंधित बीमारियों का भी खतरा रहता है।

शराब–सिगरेट के बाद इस वजह से हो रही हैं सबसे ज्यादा मौतें

अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की रिपोर्ट के अनुसार लाइफस्टाइल की जिन समस्याओं के कारण सबसे ज्यादा मौतें रिपोर्ट की जाती रही हैं उनमें सिगरेट पीने के कारण होने वाली बीमारियां प्रमुख हैं, शराब को मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण पाया गया है। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि शराब–सिगरेट के होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए नमक के अधिक सेवन को कारण पाया गया है। नमक के अधिक सेवन से हार्ट और शरीर में इंलामेशन से संबंधित कई प्रकार की गंभीर और जानलेवा बीमा. रियों का खतरा हो सकता है।

नमक के अधिक सेवन के कारण बढ़ती बीमारियां

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के विशेषज्ञों ने कहा, हमें रोजाना दो ग्राम से अधिक मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को पहले से हार्ट या ब्लड प्रेशर की समस्या रही है उन्हें इसकी मात्रा 1500 मिलीग्राम से भी कम रखना चाहिए। यानि एक दिन में एक से डेढ़ चम्मच नमक के बराबर है। आप जितना ज्यादा नमक खाते हैं, ब्लड प्रेशर और इसके कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा उतना अधिक हो जाता है। ये हृदय रोगों का भी प्रमुख कारण है जिसके मामले वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है।

नोट- आप का सामना की हेल्थ,युवा, शिक्षा सामना कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से पेशेवर पत्रकारों द्वारा बातचीत के आधार पर पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किये जाते है। आप का सामना लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी,शिक्षा,जॉब के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर,शिक्षक से परामर्श लें।

यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं, तो सभी धर्मों के धर्मग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए।
-डॉ० भीमराव अंबेडकर

संपादकीय

भारत-भूटान संबंध

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूटान यात्रा सार्थक होते हुए भी काफी हद तक प्रतीकात्मक थी। एक सप्ताह पहले दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे की श्री मोदी के साथ लंबी द्विपक्षीय बातचीत ने इस किस्म की दूसरी एक के बाद एक यात्रा की जरूरत को समाप्त कर दिया था। भूटान की पंचवर्षीय योजना के लिए भारत की सहायता को 5,000 करोड़ रुपये से दोगुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने का एलान महत्वपूर्ण था, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और यह एलान बाद में, चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी किया जा सकता था। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण भूटान के राजा द्वारा श्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान करना था। इस पुरस्कार का एलान 2021 में कोविड–19 महामारी के दौरान भारत द्वारा दिए गए समर्थन के लिए किया गया था और अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तथ्य यह है कि भारत में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू होने, अपने चुनाव अभियान की व्यस्तता और भूटान में खराब मौसम की वजह से इस कार्यक्रम के लगभग पटरी से उतरने के बावजूद श्री मोदी का इस यात्रा पर जाना, यह दर्शाता है कि यह दौरा कितना महत्वपूर्ण था। इस दौरे का प्रतीकात्मक संदेश त्रि–आयामी थारू पहला, यह कि भारत भूटान के विकास लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खासतौर से, आगामी गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी को लेकर। यह एक ऐसी परियोजना है जिसको भारत द्वारा अपने पड़ोसी देश को वित्तीय सहायता में वृद्धि करने से फायदा मिलने की संभावना है। दूसरा, भूटान भारत की सड़क, रेल एवं एकी.त जांच बिंदुओं (चेक प्वाइंट) और भारत के ग्रिड पर ऊर्जा के आदान–प्रदान से भी जुड़ी बुनियादी ढांचे की पहल का एक अभिन्न हिस्सा है। ये दोनों ही पहलू भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बीच उप–क्षेत्रीय व्यापार और आवाजाही को बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा, भारत चीन के साथ भूटान की बढ़ती भागीदारी को लेकर सचेत है। ये दोनों देश सीमा समझौते को जल्द ही पूरा कर लेने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन भूटान व्यापार और निवेश जैसे जुड़ाव के अन्य क्षेत्रों में बीजिंग को जगह देने का इरादा नहीं रखता है। चीन ने भारत के अन्य करीबी पड़ोसी देशों में व्यापार और निवेश के क्षेत्र में घुसपैठ की है।

नतीजतन, विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने चीन–भूटान सीमा वार्ता पर पूछे गए एक सवाल को भले ही खारिज कर दिया हो और उसके प्रति उदासीनता का दिखावा किया हो, लेकिन वे सवाल महत्वपूर्ण हैं। भूटान के पश्चिम में स्थित डोकलाम में भूमि की संभावित अदला–बदली के बारे में चीन–भूटान वार्ता को जहां वास्तव में भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक खतरे के रूप में देखा जा रहा है, वहीं भूटान के पूर्व में स्थित इलाकों पर चीन का दावा अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा को जोडने वाली परियोजनाओं को खतरे में डाल सकता है। हाल की रिपोर्टें, जिनका विदेश मंत्रालय ने खंडन नहीं किया है, इस बात का संकेत करती हैं कि भूटान ने भारत से चीन के साथ अपनी सीमा वार्ता पूरी होने तक उन परियोजनाओं पर धीमी गति से आगे बढने के लिए भी कहा है। लिहाजा, श्री मोदी के इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण संदेश बदलाव के समय में एकजुट होने का था। अपना पुरस्कार स्वीकार करते हुए, श्री मोदी ने भारत–भूटान संबंधों को अटूट बताया। भारत और भूटान को आने वाले दिनों में अपने–अपने देश के भीतर आर्थिक और सामाजिक उथल–पुथल के साथ–साथ पड़ोस में पैदा होने वाली चुनौती के मद्देनजर अपने संबंधों के स्थायित्व को बरकरार रखने के लिए एकजुटता के इस कदम पर और भी ज्यादा जोर देने की जरूरत होगी।

इस्लामिक स्टेट से जुड़ी चिंताएं, मॉस्को में आतंक

बीते 22 मार्च को मॉस्को के बाहरी इलाके में स्थित क्रोकस सिटी हॉल पर हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 137 लोग मारे गए थे। यह हमला इन चिंताओं को रेखांकित करता है कि इस्लामिक स्टेट (आईएस), जिसका सीरिया और इराक में वास्तविक खिलाफत छह साल पहले नष्ट कर दिया गया था, एक बार फिर अपना सिर उठाने की राह पर है। जनवरी में, इस सुन्नी जिहादी समूह की अफगानिस्तान स्थित शाखा इस्लामिक स्टेट–खोरासान (आईएस–के) ने ईरान के करमान में दोहरे बम विस्फोट किए थे, जिसमें कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम को निशाना बनाया गया था। जनरल सुलेमानी की जनवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हत्या कर दी गई थी। इन बम विस्फोटों में कम से कम 80 लोग मारे गये थे। तब से, आईएस ने तुर्की, सीरिया और अफगानिस्तान को निशाना बनाया है और मॉस्को की गोलीबारी इसकी बढ़ती आतंकी क्षमताओं की ओर इशारा करती है। रूसी अधिकारियों ने चार ताजिक नागरिकों पर आरोप लगाया है। आईएस–के, जिसकी स्थापना 2015 में अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में स्थापित हुई थी, मुख्य रूप से मध्य एशियाई आतंकवादियों से मिलकर बना है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद यह शाखा प्रमुखता से उभरी। तब से, आईएस–के ने अफगानिस्तान के शिया अल्पसंख्यकों पर हमला किया है और मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान के उन ताजिक एवं उज़्बेक अल्पसंख्यकों के कट्टरपंथी युवाओं को मिलाकर विभिन्न गुटों का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की है, जो तालिबान के पश्तून निजाम से नाराज हैं। ये नेटवर्क अब मजबूत हो रहे हैं।

हाल के महीनों में आईएस–के ने रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ दुष्प्रचार वाले वीडियो चलाए हैं। आईएस का दावा है कि रूसियों ने अफगानिस्तान, चेचन्या और सीरिया में मुसलमानों का खून बहाया है। सीरिया में, 2015 में रूस के हस्तक्षेप ने गृह युद्ध को राष्ट्रपति बशर अल–असद के शासन के पक्ष में मोड़ दिया था, जिन्हें आईएस उखाड़ फेंकना चाहता था। एक के बाद एक हो रहे हमले यूरेशियन क्षेत्र के लिए सुरक्षा संबंधी एक गंभीर चुनौती पैदा करते हैं। खासकर रूस के लिए।

चुनावी बॉन्ड योजना, भ्रष्ट योजना

चुनावी बॉन्ड के खरीदारों व चंदा–दाताओं के मिलान से सांठगांठ, भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा डेटा की आखिरी किस्त जारी किये जाने के बाद, अब उस चुनावी वित्तपोषण की तकरीबन पूरी तस्वीर हासिल करना संभव हो गया है जो पहले एक गुप्त जरिया हुआ करता था। एसबीआई को कॉरपोरेट व व्यक्तिगत चंदा–दाताओं द्वारा खरीदे गये और बाद में राजनी. तिक दलों द्वारा भुनाये गये चुनावी बॉन्डों के लिए विशिष्ट संख्याओं (यूनिक नंबरों) का डेटा जारी करना पड़ा। इस डेटा (पहले दिया गया डेटा चंदा–दाताओं और दलों को आपस में जोड़ सकने वाली विशिष्ट संख्याओं के बगैर था) को जारी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई को दो बार कोंचना पड़ा।

यह बैंक के रवैये पर उंगली उठाता है जिसने शुरू में यह सूचना जारी करने के लिए 30 जून, 2024 तक, यानी आम चुनाव के बाद की मोहलत मांगी थी। दूसरी तरफ, बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और उन्हें भुनाने वाले दलों से जुड़ी सूचना के दो सेटों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक सरल डेटा–मिलान करने में समाचार संगठनों को बस चंद घंटे लगे। डेटा पर एक सरसरी नजर डालने से ही उस दलील की व्यर्थता जाहिर होती है जो केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्डों की गोपनीयता की जरूरत के लिए पेश की थी, लेकिन जिसे शीर्ष अदालत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया।

कुछ राजनीतिक दलों को बड़े चंदे दिये जाने और बॉन्ड खरीदारों को बुनियादी ढांचे के भारी राशि वाले ठेके मिलने के बीच एक स्पष्ट सह–संबंध नजर आता है।

कुछ मामलों में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या आयकर विभाग द्वारा जांच या कार्रवाई का सामना कर रहे प्रतिष्ठानों (एंटिटीज) और बाद में इन प्रतिष्ठानों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा बॉन्ड खरीदे जाने के बीच एक मजबूत सह–संबंध है। खासतौर पर, ऐसे कई चंदा–दाताओं द्वारा खरीदे गये बॉन्ड बाद में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा भुनाये गये।

शीर्ष 19 फर्मों (दिये गये चंदों की संचयी राशि के आधार पर) ने 2019 के मध्य से फरवरी 2024 तक (इस अवधि में 22 फर्मों ने 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के चंदे दिये), अन्य दलों के साथ–साथ, भाजपा को निरपवाद रूप से चंदा दिया। यह बताता है कि इन बॉन्डों का इस्तेमाल सत्ता प्रतिष्ठान की कृपा पाने के एक उपकरण की तरह किया गया।

इन बॉन्डों के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या की एसबीआई के हाथों में मौजूदगी (जिससे उसके लिए लेन–देन की ऑडिट ट्रेल रखना संभव हो सकता था) और वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ बॉन्डों को उनकी मियाद (खरीद के 15 दिन के भीतर) खत्म होने के बाद भुनाये जाने की इजाजत दिये जाने ने यह दिखाया कि इस योजना ने सत्तारूढ़ दल के लिए अनुचित फायदे की स्थिति पैदा की थी।

यह साफ है कि इन बॉन्डों ने चुनाव अभियान और दलीय वित्तपोषण को सत्तारूढ़ दल के पक्ष में बहुत ज्यादा झुका दिया था। साथ ही, इसने चंदा देने की अनैतिक प्रेरणाओं पर भी पर्दा डाले रखा था।

अब यह सिविल सोसाइटी पर निर्भर है कि वह मतदाताओं को इस योजना की असलियत के बारे में बताये और चंदों के एकांगीपन को लेकर सवाल खड़े करे। यह व्यवस्था को साफ–सुथरा करने की दिशा में बस पहला कदम होगा।

राज्यपालों के कृत्य

संविधान के पालन में राज्यपालों की आनाकानी पर केंद्र को चिंतित होना चाहिए। तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि का आचरण पिछले कुछ समय से संवैधानिक रूप से शंकास्पद है। ताजा मामला उनके द्वारा के. पोनमुडी को तमिलनाडु मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल करने की इजाजत देने से इनकार करने का है, जो पूरी तरह अनुचित कदम के रूप में सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट से कड़ी आलोचना के बाद, रवि ने पोनमुडी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। भ्रष्टाचार के एक मामले में पोनमुडी की दोष–सिद्धि पर शीर्ष अदालत ने हाल ही में रोक लगायी थी, जिसके परिणामस्वरूप विधानसभा का सदस्य होने की उनकी पात्रता बहाल हो गयी। रवि का यह रुख कि दोष–सिद्धि पर रोक के आधार पर पोनमुडी को मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल करना संवैधानिक नैतिकताय के खिलाफ होगा, कानूनी तौर पर टिकने वाला नहीं था। राज्यपाल की व्याख्या के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए दोष–सिद्धि के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ द्वारा लगायी गयी रोक सिर्फ एक किस्म की अंतरिम राहत थी और इसका मतलब यह था कि दोष–सिद्धि श्बरकरार, लेकिन अक्रियान्वित थीच और यह इसे पलटे जाने के बराबर नहीं था। यह व्याख्या काफी शंकास्पद थी, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक दोष–सिद्धि से उपजे कानूनी नतीजे (विधायक होने की पात्रता और इसलिए, मंत्री होने की पात्रता छिन जाना) दोष–सिद्धि पर रोक लगते ही निलंबित हो जाते हैं। दोष–सिद्धि पर रोक लगते ही संसद और राज्य विधानसभाएं दोषी करार व्यक्ति की सदस्यता बहाल करती हैं, भले ही उनकी सीटें खाली घोषित की जा चुकी हों। राज्यपाल का श्नैतिकताय और सुशासन के सिद्धांतों का वैधता के साथ घालमेल करना, जाना–बूझा प्रतीत हुआ।

अब जबकि रवि की डीएमके शासन को परेशान करने के लिए नये–नये तरीके खोजने की प्रवृत्ति ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है, दो चीजें साफ दिखती हैं रू अपने पद की सीमाओ. ं को स्वीकार करने की उनकी अनिच्छा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने राज्यपालों की खिंचाई के बढ़ते मामलों पर कदम उठा पाने में केंद्र सरकार की विफलता। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया था कि रवि ने अपने पास लंबित विधेयकों का निपटारा तभी किया जब उसने उनकी लंबी निष्क्रियता पर सवाल खड़े किये। ताजा मामले में उन्होंने शीर्ष अदालत को यह पूछने के लिए पर्याप्त कारण प्रदान किया कि, अगर राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते, तो राज्य एक सांविधानिक अदालत का दरवाजा खटखटाने के सिवाय क्या करे? चीजें इस मुकाम पर पहुंच गयी हैं कि सिर्फ एक मुखर अदालत ही राज्यपालों को अनुशासित कर सकती है।

राज्यपालों के आचरण से जुड़ी मुक. दमेबाजी की बहुलता को देखते हुए, यह बात परेशान करने वाली है कि केंद्र को उपचारात्मक उपायों के लिए कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, जबकि उसका कर्तव्य उन राज्यपाला. ं को बदलना होना चाहिए जो संविधान पालन के आदतन विरोधी हैं। इसकी एकमात्र व्याख्या यह है कि उनका आचरण संवैधानिक मानदंडों से नहीं, बल्कि उस राजनीतिक जिम्मेदारी से चालित है जो उन्हें अपने नियोक्ताआ. ं द्वारा दी गयी है।

एआई पर नियंत्रण लगाना निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी

टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट और वॉट्सएप के बाद एआई और डीपफेक के अखाड़े पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग परम्परागत मामलों में ही दंडनायक की भूमिका निभा रहा है। विदेशी टेक कंपनियों के फर्जीवाड़े के आगे पूरा सिस्टम फेल–सा है।

सीनेट की खुफिया समिति के सदस्य बेनेट के अनुसार चुनावों में दुष्प्रचार और विमर्श में जहर घोलने का टेक कंपनियों का लम्बा इतिहास रहा है। उन्होंने अमेरिकी टेक कम्पनियों से भारत के चुनावों से जुड़ी नीतियों, सामग्री–नियंत्रण और एआई की पहचान वाले उपकरणों की जानकारी मांगी है।

यूरोपीय यूनियन की संसद ने एआई को रेगुलेट करने के कानून को मंजूरी दी है, लेकिन भारत में ठोस कानून नहीं हैं। स्वतंत्र–निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग को इन मुद्दों पर चर्चा और कार्रवाई की जरूरत है।

माइक्रोसॉट की रिपोर्ट के अनुसार चीन एआई और साइबर समूहों के माध्यम से भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के चुनावों को बाधित करने की तैयारी कर रहा है। झूठे और मनगढ़ंत मीम्स, फोटो, इंटरव्यू और वीडियोज को सोशल मीडिया के फर्जी खातों से प्रसारित करके जनता को बड़े पैमाने पर गुमराह करना आसान हो गया है। इससे मतदाताओं के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। अमेरिका और यूरोपीयन यूनियन के चुनावों में एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए मेटा जैसी कंपनियों ने विशेष दस्ते तैनात किए हैं। लेकिन भारत में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पास इन जटिल मुद्दा. ं से निपटने के लिए जानकारी, ट्रेनिंग, तकनीक और अधिकारों का अभाव है।पिछले 120 सालों के मौसम रिकॉर्ड को डिजिटल करके एआई और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से भारत में मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। उसी तरह से डेटा, एआई और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से प्रचार, मतदान और चुनाव परिणाम प्रभावित हो रहे हैं। अधिकांश टेक कंपनियां एआई के कारोबार में भी हैं, जो डेटा के अवैध इस्तेमाल पर आधारित हैं। ये सर्च और ब्राउजर हिस्ट्री, क्लाउड डेटा, शेयर्ड वीडियो, गेमिंग साइट्स, शॉपिंग साइट्स जैसे 500 से ज्यादा तरीकों से करोड़ों जनता का डेटा इकठ्ठा कर रही हैं। एआई के ओपन सोर्स सॉटवेयर से कंटेंट और नेताओ. के भाषणों में मनमानी छेड़छाड़ की जा सकती है।

हथियारों की मदद न मिलना बड़ी वजह, इस साल यूक्रेन की पहली पंक्ति की सेना को तबाह कर सकता है रूस

dhoA यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इस बीच एक विदेशी मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि हथियारों की कमी के कारण यूक्रेन में स्थिति मुश्किल हो गई है। रूसी सेना अब यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ती दिख रही है। इस वजह से रूस इस गर्मी में यूक्रेनी सेना की पहली पंक्ति को ध्वस्त कर सकता है। यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल भी कथित रूप से कमजोर हो रहा है।

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यूक्रेन और इस्राइली सहयोगियों को सहायता उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने हाल ही में आंखें मूंदने के लिए अपने देश के सहयोगियों की आलोचना की थी।

यूक्रेन को भारत से आस

युद्ध को दो साल पूरा होने पर यूक्रेन के उप विदेश मंत्री इरीना बोरोवेत्स ने कहा था कि भारत को शांति–खोज समाधान का हिस्सा बनना ही होगा। भारत अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा है, इसलिए उससे कई उम्मीदें भी हैं। भारत के रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे संबंध हैं। बोरोवेत्स ने कहा कि सबसे पहले, भारत एक वैश्विक नेता है, जो यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। वह रूस–यूक्रेन जंग के शांतिपूर्ण समाधान खोजने में अधिक मुखर होकर कार्रवाई कर सकता है। बोरोवेत्स ने कहा, पीएम मोदी ने गत वर्ष उज्बेकिस्तान में रूसी राष्ट्रपति से यह तक कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। इस बयान को पूरी दुनिया का समर्थन मिला। उन्होंने कहा, यूक्रेन ने मार्च में स्विट्जरलैंड में होने वाले ग्लोबल पीस समिट में भारत को आमंत्रित किया है।

रूस के राष्ट्रपति भी पहले ही पीएम मोदी से जता चुके हैं उम्मीद

इससे पहले, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि कि पीएम मोदी शांतिपूर्ण तरीकों से रूस–यूक्रेन विवाद को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम पीएम मोदी के रूख को समझते हैं। हमने कई मौकों पर इसका बार–बार उल्लेख किया। मुझे पता है कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे को शांति से हल किया जा सके। हम इस पर गहराई से बात करेंगे। उन्होंने भारत–रूस संबंधों के लिए आभार व्यक्त किया था। हम दोनों विकास के नए आयाम छू रहे हैं। पुतिन ने भारत और रूस की साझेदारी पर भी बात की थी।

ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों पर नए प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका

okf'kxVu ईरान द्वारा इस्राइल पर हमले के बाद से पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस हमले की कई देशों ने व्यापक निंदा की है। हालांकि ईरान ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि उसने इस्राइल द्वारा सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया है। इसी बीच, अमेरिका ने कहा है कि वह ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका ईरान के मिसा. इल और ड्रोन कार्यक्रमों पर नए प्रति. बंध लगाएगा इसके अलावा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) और ईरान के रक्षा मंत्रालय का समर्थन करने वाली संस्थाओं पर भी आने वाले दिनों में नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

सुलिवन ने ताजा बयान में कहा कि इस्राइल के खिलाफ ईरान के हवाई हमले के बाद राष्ट्रपति बाइडन जी7 सहित सहयोगियों और भागीदारों और कांग्रेस में द्विदलीय नेताओं के साथ व्यापक प्रतिक्रिया पर समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिना. ` में अमेरिका ईरान को निशाना बनाते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाएगा। जेक ने अपील करते हुए कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों से भी ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की उम्मीद करता है। अमेरिका ईरान की मिसाइल और यूएवी क्षमताओं की प्रभावशीलता को और कम करने के लिए मध्य पूर्व में वायु और मिसाइल रक्षा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को और मजबूत करने के लिए अपना काम जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे सहयोगी जल्द ही प्रति. बंधों का पालन करेंगे।

अपने ताजा बयान में उन्होंने यह भी कहा कि हम वायु और मिसाइल रक्षा के सफल एकीकरण को और मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए रक्षा विभाग और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जरिए काम कर रहे हैं और हम इसे आगे भी जारी रखेंगे। इससे हम पूरे मध्य पूर्व में ईरान की मिसा. इल और यूएवी क्षमताओं की प्रभावशीलता को और कम कर पाएंगे। ईरान पर नए प्रतिबंधों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि नए प्रति. बंध और अन्य उपाय ईरान की सैन्य क्षमता और प्रभावशीलता को नियंत्रित करने और कम करने के लिए हैं। ये उस पर दबाव बनाने के लिए लगातार जारी रहेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका ने बीते तीन सालों में मिसाइल और ड्रोन से संबंधित प्रतिबंधों के अलावा, आतंकवाद से जुड़े 600 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं।

इनमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती और कताइब हिजबुल्लाह सहित कई अन्य आतंकवादी समूह हैं। उनपर ये प्रति. बंध जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अमे. रिका ईरानी सरकार को उसके दुर्भावनापूर्ण और अस्थिर करने वाले कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए हम दुनिया भर के सहयोगियों और साझेदारों और कांग्रेस के साथ समन्वय में कार्रवाई जारी रखने में संकोच नहीं करेंगा।

इससे पहले, 14 अप्रैल को, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस्राइल के खिलाफ ईरान के हमलों पर अपडेट के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से मुलाक. ात की थी। उससे पहले शनिवार को उन्होंने इस्राइल पर ईरानी ड्रोन हमलों के मद्देनजर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की थी।

ईरान- इस्राइल में किसकी सेना ज्यादा मजबूत, दोनों देशों के पास कौन-कौन से हथियार?

ub fnYYhA ब्रिटेन ने कहा है कि वह इस्राइल को हथियारों का निर्यात करना जारी रखेगा। इस बढ़ते तनाव के बीच दोनों देश अपनी सैन्य क्षमता का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आइये जानते हैं कि इस्राइल की सेना कितनी मजबूत है? ईरानी सेना की ताकत कितनी है? दोनों देशों के पास कौन–कौन से हथियार हैं?

ईरान और इस्राइल में किसकी सेना ज्यादा मजबूत?

ग्लोबल फायर पावर संस्था मौजूदा उपलब्ध मारक क्षमता के आधार पर देशों की रैंकिंग जारी करती है। किसी देश के पावरइंडेक्स स्कोर को निर्धारित करने के लिए 60 से अधिक कारकों का उपयोग करके यह रैंकिंग की जाती है।

2024 के लिए जारी की गई ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के अनुसार, ईरान की सैन्य क्षमता दुनिया में 14वीं सबसे बड़ी है। इसका पावरइंडेक्स स्कोर 0. 2269 आंका गया है। 0.0000 का स्कोर श्परफेक्टश् माना जाता है।

वहीं दूसरी ओर इस्राइल की सैन्य क्षमता देखें तो इसकी सेना दुनिया में 17वें स्थान पर है। इस्राइल का पावरइंडेक्स स्कोर 0.2596 है।

किसके पास कितने सैनिक हैं?

8.7 करोड़ आबादी वाले ईरान के पास 56 फीसदी यानी 4.9 करोड़ मैन पावर है। ईरान की सेना में सैनिकों की संख्या 11.80 लाख है। इनमें से 6.10 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी हैं, जबकि रिजर्व कर्मी 3.50 लाख हैं। ईरान में अर्धसैनिक 2.20 लाख, वायु सेना कर्मी 42 हजार, सैन्य कर्मी 3.50 लाख और नौसैनिक 18.5 हजार हैं।

इस्राइल की आबादी 90 लाख है और इसके पास 42 फीसदी यानी 37 लाख मैन पावर है। इस्राइली सेना में सैनिकों की संख्या 6.7 लाख है। इनमें से 1.70 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी हैं, जबकि रिजर्व कर्मी 4.65 लाख हैं। इस्राइल में अर्धसैनिक 35 हजार, वायु सेना कर्मी 89 हजार, सैन्य कर्मी 5.26 लाख और नौसैनिक 19.5 हजार हैं।

दोनों देशों की सेनाओं के पास क्या–क्या है?

ईरान के सेना के पास कुल 1,996 टैंक का स्टॉक है। इसके अलावा ईरानी सेना के पास 65,765 युद्धक वाहन, 580 स्व–चालित तोपखाना, 2,050 टोड आर्टिलरी और 775 मल्टिपल रॉकेट लॉन्चर आर्टिलरी हैं। इस्राइली सेना (आईडीएफ) की क्षमता देखें तो इसके पास कुल 1370 टैंक हैं। इसके अलावा आईडीएफ के पास 43,407 युद्धक वाहन, 650 स्व–चालित तोपखाना, 300 टोड आर्टिलरी और 150 मल्टिपल रॉकेट लॉन्चर आर्टिलरी हैं। किसकी वायु सेना कितनी ताकतवर है?

25 xuk T;knk lifUk tCrh] 86 xuk T;knk Nkiekjh chr nl o"kk e bMh u dh rkcMrkM dkjokb

ub fnYYhA बीते 10 वर्षों में भाजपा शासनकाल के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सक्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 10 वर्षों में धन शोधन रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत ईडी की छापेमारी 86 गुना बढ़ गई है। ईडी ने इस दौरान 25 गुना ज्यादा संपत्ति जब्त की है। ये आंकड़े 2014 से पहले की यूपीए सरकार की तुलना में हैं।

बीते 10 वर्षों में ईडी की सक्रियता में आया गजब उछाल

एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2014 से मार्च 2024 के बीच के आंकड़ों की जुलाई 2005 से लेकर मार्च 2014 तक के आंकड़ों से तुलना करने पर पता चलता है कि ईडी की सक्रियता में बीते 10 वर्षों में काफी तेजी आई है। पीएमएलए कानून को साल 2002 में बनाया गया था और 1 जुलाई 2005 को इसे लागू कर दिया गया था। यह कानून टैक्स की चोरी रोकने, काले धन और धन शोधन पर रोकथाम के लिए बनाया गया था। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार, विरोधियों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि सत्ताधारी दल का एजेंसी पर कोई दबाव नहीं है और यह स्वतंत्र रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है।

आंकड़े कह रहे कहानी

आंकड़ों के अनुसार, ईडी ने बीते 10 वर्षों में पीएमएलए कानून के तहत 5,155 मामले दर्ज किए हैं, जो कि यूपीए सरकार में किए गए 1,797 मामलों की तुलना में तीन गुना ज्यादा है। ईडी की जांच में अभी तक पीएमएलए कानून के तहत 63 लोगा. ` के खिलाफ दोषसिद्धि हुई है। ईडी द्वारा पहली बार 2014 में ही एक मामले में दोषसिद्धि हुई थी। भाजपा सरकार में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7,264 छापेमारी की, जबकि 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 84 छापेमारी की थी। इस तरह भाजपा सरकार में ईडी ने 86 गुना ज्यादा छापेमारी की हैं।

ईडी ने बीते दशक में 755 लोगों को गिरतार किया है और 1,21,618 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जबकि बीती सरकार में ईडी ने 29 लोगों को गिरतार किया और सिर्फ 5,086 करोड़ रुपये की संपत्ति ही जब्त की थी। इस तरह ईडी की गिरतारी 26 गुना ज्यादा और संपत्ति जब्ती 24 गुना ज्यादा हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीते 10 वर्षों में 1,971 कुर्की के आदेश जारी किए हैं, जबकि पहले ऐसी 311 कार्रवाई की गई थी। ईडी ने 12 गुना ज्यादा चार्जशीट दाखिल की हैं। ईडी ने 36 मामलों में 63 लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध किया है और 73 चार्जशीट का निपटारा किया है। 2005 से 2014 के दौरान ईडी ने किसी मामले में कोई दोषसिद्धि नहीं की थी।

ईडी ने बीते 10 वर्षों में पीएमएलए कानून के तहत 2,310 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है, जबकि पहले सिर्फ 43 लाख रुपये नकद जमा किए गए थे।

ईडी ने चार आरोपियों के भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है और विजय माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई चल रही है। ईडी ने इंटरपोल के 24 रेड नोटिस जारी कराए हैं, जबकि पहले कोई नोटिस जारी नहीं कराए गए थे।

बंगाल में एनआरसी लागू न होने देने का एलान, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जारी किया घोषणा-पत्र

dkydkrkA लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। पार्टी के नेता डेरेक ओ ब्रायन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणापत्र जारी किया। पार्टी के घोषणापत्र में बंगाल में एनआरसी लागू न होने देने का एलान किया गया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें लिखा गया है कि श्हमे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी करते हुए खुशी हो रही है। दीदी की शपथ के साथ हम हर भारतीय को रोजगार की गारंटी, सभी को घर, मुत एलपीजी सिलेंडर, किसानों को एमएसपी, एससी–एसटी और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की कसम खाते हैं। हम साथ में भाजपा के जमींदारों को उखाड़ फेकेंगे और सभी के सम्मानित जिंदगी सुनिश्चित करेंगे।

टीएमसी के घोषणापत्र के बड़े एलान

टीएमसी ने अपने घोषणापत्र में सीएए कानून को निरस्त करने और एनआरसी को लागू न होने देने का वादा किया है। साथ ही पूरे देश में कहीं भी समान नागरिक संहिता को भी लागू नहीं करने का भी वादा किया गया है।

टीएमसी के घोषणापत्र में सभी नौकरी कार्ड धारकों को 100 दिन की रोजगार गारंटी देने की बात कही गई है और कामगारों को एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन देने की बात कही गई है।

सभी बीपीएल परिवारों को हर साल 10 एलपीजी सिलेंडर मुत दिए जाएंगे।

सभी राशन कार्ड धारकों को हर महीने पांच किलो राशन मुत दिया जाएगा। साथ ही राशन की लोगों को घर पर डिलीवरी की जाएगी और इसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा।

एससी,एसटी और ओबीसी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति की रकम बढ़ाई जाएगी।

60 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।

टीएमसी के घोषणापत्र में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर किसानों को एमएसपी दी जाएगी। एमएसपी फसल की औसत लागत से पचास फीसदी अधिक दी जाएगी।

पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को कम किया जाएगा और कीमतों में उतार–चढ़ाव से बचने के लिए एक कीमत स्थिर करने वाला फंड स्थापित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपये तक की क्रेडिट कार्ड लिमिट दी जाएगी। साथ ही 25 साल तक सभी स्नातकों और डिप्लोमाधारकों को हर महीने अप्रेंटिस दी जाएगी। ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित किया।

स्वामी,सम्पादक,प्रकाशक व मुद्रकः संतोष कुमार शुष्टा, आकाश व्यू, छकड़ायल रोड, कमला नगर, संजौली शिमला हि0 प्र0 – 171006 से प्रकाशित तथा सिग्मा प्रिंटर ब्लॉक न.6,शॉप न.170 एसडीए कॉम्पलेक्स कसुम्पटी शिमला से मुद्रित। किसी भी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र शिमला ही मान्य होगा। मोबाईलः 09418453928,9805192400 e-mail: aapkasaamna@gmail.com